Poonam Shodh Rachna (ISSN 2456-5563)
(A Multidisciplinary, Peer Reviewed And Refereed Journal)
Vol.3, Issue.II, February 2024, Pc : PSR-2402017
Special Issue of International Seminar on Emerging Trends in Humanity and Social Sciences Research

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव: गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास पर जोर

मीना कुमारी, लेक्चरर,
बाबा खेतानाथ महिला टी टी कॉलेज
भीटेरा, बहरोड़, कोटपुतली

संक्षेप

कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है जिससे दुनिया की कई आबादी गरीब हो गई है। इसके अलावा महामारी ने आर्थिक और सामाजिक नीतियों के संबंध में कुछ अनिश्चितताएं उत्पन्न की हैं। यह घटना हाल ही में दुनिया भर में हर सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यह वर्तमान अध्ययन एक पैनल अध्ययन में व्यक्तिगत देशों के विषम प्रभावों पर विचार करके गरीबी उन्मूलन और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद पर महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहता है। प्रेरणा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को उजागर करना है। हालाँकि इस अध्ययन में 170 देशों का उपयोग किया गया है और अर्थमितीय पैनल तकनीकों जैसे ओएलएस और मजबूत न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन विधियों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि कई लोगों की कठोरता और बीमारी के संकुचन ने गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव डाला है। फिर भी अब तक दर्ज की गई मौतों का गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह विकास जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के सार का संकेत देता है क्योंकि यह आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में बाधा डालता है। अध्ययन में सिफारिश की गई है कि सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार में निवेश करें और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करें जो गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास में सुधार के लिए विकास को बढ़ावा दे सके।

योगदान/मौलिकता: यह अध्ययन मौजूदा साहित्य में योगदान देता है और वैश्विक संदर्भ में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव को प्रस्तुत करता है।

परिचय

वैश्विक कोविड-19 महामारी ने चौंकाने वाली गति से दुनिया की लाखों आबादी को संक्रमित किया है। बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए गतिशीलता पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण इसके उद्भव ने दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है और नीचे ला दिया है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया ने ऐसा अनुभव नहीं देखा है। हालाँकि बिगड़ती मानव और स्वास्थ्य स्थितियों से उत्पन्न झटकों के कारण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह महामारी न केवल एक स्वास्थ्य संकट है बल्कि बड़े पैमाने पर जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रभाव के कारण सामाजिक और आर्थिक संकट भी है। इसके अलावा महामारी का प्रभाव अलग-अलग देशों में अलग-अलग होगा और इससे वैश्विक स्तर पर असमानताएं और गरीबी बढ़ने की संभावना है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई प्रगति को रोक देगा जिस पर अधिक ध्यान देने और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सरकोडी और ओवसु के अनुसार मानव जीवन और बड़े पैमाने पर देशों पर पर्यावरण-स्वास्थ्य-आर्थिक प्रभाव का गठजोड़ महामारी के उद्भव के कारण आवश्यक हो गया है। चूँकि वैश्विक महामारी ने पर्यावरण स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के परिणामों के बारे में बहुत अधिक

चिंता दिखाने की आवश्यकता ला दी है। 18 दिसंबर 2020 तक दुनिया भर में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 72851747 है और मौतों की संख्या 1643339 है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका को 16446844 की कुल संख्या के साथ सबसे अधिक नुकसान हुआ है। भारत ब्राजील रूस और फ्रांस दुनिया में सबसे अधिक मामलों वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं।

वैश्विक महामारी ने एक साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति दोनों को बाधित कर दिया है। आपूर्ति पक्ष के आधार पर संक्रमण के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ जिससे श्रम उत्पादकता और आपूर्ति कम हो गई। गतिशीलता सामाजिक दूरी और व्यापार बंद होने पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया। मांग पक्ष पर संगरोध रुग्णता और बेरोजगारी के कारण आय में कमी और छंटनी हुई और खराब आर्थिक संभावनाओं के कारण फर्मों के निवेश और घरेलू खपत में कमी आई। इसके अलावा यात्रा प्रतिबंध लॉकडाउन आंदोलन प्रतिबंध सामाजिक गड़बड़ी और अन्य तरीकों से सार्वजनिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्थानों को बंद करने जैसे कड़े उपायों ने आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रभावित किया हैं।

वैश्विक आर्थिक संभावनाओं (विश्व बैंक 2020 के अनुसार मौद्रिक और राजकोषीय प्रभाव नीति सहायता से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों के असाधारण हस्तक्षेप के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संकुचन की परिकल्पना करती है। इसके बावजूद अनुमान है कि महामारी के परिणाम स्कूली शिक्षा और काम के नुकसान कम निवेश और वैश्विक आपूर्ति और व्यापार संबंधों के विघटन के परिणामस्वरूप मानव पूंजी को नष्ट करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। सरकोडी और ओवसु का तर्क है कि सामाजिक दूरी और लॉकडाउन के माध्यम से कोविड-19 वायरस के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों और कड़े उपायों का वैश्विक आबादी पर गंभीर आर्थिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। लॉकडाउन प्रभाव ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने में जबरदस्त योगदान दिया है और उत्सर्जन में कमी आई है। भले ही महामारी ने कुछ तबाही मचाई हो लेकिन इसने आर्थिक विकास की गति में गिरावट को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक राहत उपायों की आवश्यकता के लिए बड़े सबक दिए हैं। महामारी के प्रभाव की लंबाई पथ और सीमा के बारे में अत्यधिक अनिश्चितता है जो वित्तीय स्थितियों को सख्त करने और उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास को कमजोर करने का एक दुष्चक्र विकसित कर सकता है इससे निवेश और नौकरी का नुकसान हो सकता है। संभावित प्रश्न जिनका उत्तर कोई भी अनुभवजन्य अध्ययन ढूंढेगा वे हैं देश भर में फैले प्रभावों को देखते हुए महामारी ने कौन से अभूतपूर्व झटके पैदा किए हैं पूर्वानुमानों से संबंधित अभूतपूर्व अनिश्चितता को कैसे मापें। कोविड-19 महामारी ने अनुभव की गई किसी भी अन्य महामारी की तुलना में अत्यधिक अनिश्चितता पैदा की है। कोविड-19 का स्तर विश्व स्तर पर अनुभव की गई किसी भी अन्य महामारी से कहीं अधिक है।

मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट है कि कई अध्ययनों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर महामारी के तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव की पहचान की है। हालाँकि उनमें से किसी ने भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सटीक लागत की पहचान नहीं की है। इसलिए यह वर्तमान अध्ययन उत्पादन और मानव विकास में गिरावट के संबंध में प्रति व्यक्ति दीर्घकालिक लागत का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। इसके अलावा इस वर्तमान अध्ययन में वैश्विक अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन पर महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए

एक अर्थमितीय दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है क्योंकि अधिकांश अध्ययन महामारी के विनाशकारी प्रभाव की एक वर्णनात्मक चर्चा करते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य सामान्य न्यूनतम वर्ग और मजबूत न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन विधियों जैसी अर्थमितीय तकनीकों का उपयोग करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महामारी के झटके और गरीबी उन्मूलन की मात्रा निर्धारित करना है।

उद्देश्य:

इस शोध का व्यापक उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के बहुमुखी प्रभाव को उजागर करना है। प्रत्येक उद्देश्य को इस जटिल रिश्ते के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट से उत्पन्न अर्थव्यवस्था के परिणामों की व्यापक समझ प्रदान करता है।

डिजिटल-केंद्रीकृत डेटाबेस प्रणाली स्थापित करने के अलावा सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने मूल स्थानों पर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी मदद दी। कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा कमजोरियों को बेरहमी से उजागर और बदतर बना दिया है। कुछ आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को छोड़कर भारत की 29 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन अवधि के दौरान बंद रही। चूँकि दुकानें भोजनालय कारखाने परिवहन सेवाएँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद थे इसलिए लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। वैश्विक महामारी से अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यदि अनौपचारिक क्षेत्रों पर विचार किया जाए तो अप्रैल-जून के दौरान भारत की जीडीपी संकुचन 8 % से अधिक हो सकती है। निजी उपभोग और निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि के दो सबसे बड़े इंजन हैं। कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी लहर के आने से बहुत पहले ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही थी। मानवीय संकट और सरकार के मूक व्यवहार के साथ कोविड-19 ने भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा असमानताओं को उजागर और बदतर बना दिया है। अगली 4 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में संकुचन जारी रहेगा और मंदी अपरिहार्य है। हर कोई इस बात से सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने पूरे साल के संकुचन की ओर बढ़ रही है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 2021 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान बेरोजगारी दर में 79 % से 12% की वृद्धि हुई है। एमएसएमई द्वारा अपने व्यवसाय बंद करने से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लाखों नौकरियाँ स्थायी रूप से ख़त्म हो गई हैं और खपत कम हो गई है। सरकार को स्वास्थ्य संकट से लड़ने और कोविड-19 जनित मंदी से तेजी से आर्थिक सुधार के लिए अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस आपात स्थिति से निकलने का सबसे कारगर तरीका यही है कि सरकार अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर डाल दे।

केंद्र के नो नोटिस लॉकडाउन के जवाब में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 239% गिर गई थी। 2020.21 में भारत की जीडीपी 73% घट गई। आज़ादी के बाद किसी भी वर्ष में यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे ख़राब प्रदर्शन था। फिलहाल भारत की जीडीपी विकास दर 10 फीसदी से नीचे रहने की संभावना है।

केंद्र के राजकोषीय संग्रह के लिए लेखा महानियंत्रक डेटा 2020.21 के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के सकल कर राजस्व (जीटीआर) और 14 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध कर राजस्व को इंगित करता है। कर राजस्व वृद्धि 12 प्रतिशत

होगी जिसका अर्थ है कि 2020.21 के लिए अनुमानित सकल और शुद्ध कर राजस्व क्रमशः 227 लाख करोड़ रुपये और 158 लाख करोड़ रुपये होगा।

यह बजट परिमाण की तुलना में केंद्र को 35 लाख करोड़ रुपये के कुछ अतिरिक्त शुद्ध कर राजस्व का सुझाव देता है। मुख्य अपेक्षित कमी अभी भी गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में हो सकती है। यदि हम अतीत पर नजर डालें तो गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों की वृद्धि दर अस्थिर रही है लेकिन अगर हम उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो 2020 से पहले के पांच वर्षों के दौरान उनका औसत 15% से थोड़ा कम है।

समस्याओं का विवरण:

आतिथ्य क्षेत्र: जैसा कि कई राज्यों ने स्थानीयकृत लॉकडाउन लगाया है आतिथ्य क्षेत्र को 2020 की पुनरावृत्ति का सामना करना पड़ रहा है। आतिथ्य क्षेत्र में रेस्तरां बिस्तर और नाश्ता पब बार नाइट क्लब और बहुत कुछ जैसे कई व्यवसाय शामिल हैं। वह क्षेत्र जिसने भारत की वार्षिक जीडीपी में बड़े हिस्से का योगदान दिया हैए राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और कर्फ्यू से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

पर्यटन क्षेत्र: आतिथ्य क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लाखों भारतीयों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र पहली लहर के बाद वापस उछाल मारने लगा लेकिन कोविड की दूसरी लहर तबाही के लिए वापस आ गई! पर्यटन क्षेत्र भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% योगदान देता है। इसमें होटल होम स्टे मोटल और बहुत कुछ शामिल हैं। दूसरी लहर के कारण प्रतिबंधों ने पर्यटन क्षेत्र को पंगु बना दिया है जो पहले से ही 2020 में व्यवसायों को हुए शुरुआती नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था।

विमानन और यात्रा क्षेत्र: महामारी की दूसरी लहर के दौरान विमानन और अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को बड़े पैमाने पर संघर्ष का सामना करना पड़ा। बड़ा यात्रा क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। एयरलाइंस और व्यापक यात्रा क्षेत्र के लिएए इसकी रिकवरी इस बात पर निर्भर करेगी कि भविष्य में लोग ऐसी सेवाओं का विकल्प चुनेंगे या नहीं। फिलहाल विमानन और व्यापक यात्रा क्षेत्र का परिदृश्य अच्छा नहीं दिख रहा है।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र: भारत में कोविड-19 स्थिति के कारण निकट अवधि में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दबाव बने रहने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र: दूसरी लहर के दौरान रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियों में व्यवधान आना शुरू हो गया है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया है। इस क्षेत्र के लिए 2020 तक स्थिति गंभीर नहीं रही है।

राजकोषीय घाटा: कोविड-19 महामारी का हमारे राजकोषीय घाटे और विनिवेश लक्ष्य पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 से 2022 के लिए 68% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की घोषणा की। 2020.21 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 95% हो गया जबकि पहले अनुमानित 35% था। हमारे वित्त मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में कर अनुपालन में वृद्धि के साथ-साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से बढ़ते कर राजस्व में वृद्धि करके 2025.26 तक सकल घरेलू उत्पाद का 45% राजकोषीय घाटा हासिल करने का वादा किया है। फरवरी 2020 में सरकार द्वारा प्रस्तुत मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य के अनुसार 2021.22 और 2022.23 के लिए राजकोषीय घाटा क्रमशः 33% और 31% था।

कोविड-19 महामारी का आर्थिक प्रभाव: हालाँकि नवीनतम कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से आर्थिक गिरावट को सटीक रूप से साबित करने का कोई तरीका नहीं है लेकिन अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभिक अनुमानों में अनुमान लगाया गया है कि अगर वायरस एक वैश्विक महामारी बन गया तो कई औद्योगिक राष्ट्र 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 24% खो देंगे जिससे विशेषज्ञों को 2020 के लिए अपनी वैश्विक आर्थिक विकास की उम्मीदों को लगभग 30% से कम करना पड़ेगा। 24% तक इस आंकड़े को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद लगभग 866 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया गया था जो दर्शाता है कि आर्थिक विकास में केवल 4% की गिरावट लगभग 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक उत्पादन के नुकसान के अनुरूप है। हालाँकि ये पूर्वानुमान के वैश्विक महामारी बनने से पहले और वायरस के संचरण से बचने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपर्क प्रतिबंध शुरू करने से पहले किए गए थे। तब से इस घटना के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में नाटकीय गिरावट का अनुभव हुआ है। 16 मार्च 2020 को डॉव जोन्स ने अपने मौजूदा 2300 पॉइंट रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लगभग 3000 अंकों की अपनी सबसे बड़ी एकल-दिन की गिरावट दर्ज की जो कुछ दिन पहले हासिल की गई थी।

महामारी ने आर्थिक नतीजों को बढ़ा दिया है जिससे वैश्विक संकट पैदा हो गया है जिससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और अन्य लोग मांग और आपूर्ति में व्यवधान के कारण व्यवसायों के पतन के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसलिएए महामारी न केवल एक स्वास्थ्य मुद्दा है बल्कि वैश्विक सतत विकास एजेंडे को दबाने वाला एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बहुप्रतीक्षित मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को महामारी के उद्भव के कारण जबरदस्त नुकसान हुआ। अधिकांश चिकित्सा अधिकारी यह तय करने में दुविधा में थे कि किस मरीज को जीवित रहने की जरूरत है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक उत्सुक टीके की अनुपस्थिति ने विश्व स्तर पर उच्च अनिश्चितता पैदा कर दी है क्योंकि दुनिया भर के देश किसी भी विश्वसनीय निकास रणनीति का पालन नहीं करते हैं। महामारी ने सबसे कमज़ोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को और अधिक दयनीय स्थिति में भेज दिया है जैसे कि विकलांग व्यक्तिए वृद्ध व्यक्ति युवा जातीय अल्पसंख्यक और स्वदेशी लोग। दुख की बात है कि जिन व्यक्तियों के पास आवास का कोई साधन नहीं है जैसे कि प्रवासी शरणार्थी या विस्थापित व्यक्ति महामारी के दौरान अत्यधिक पीड़ित हुए और महामारी के बाद भी पीड़ित होते रहेंगे। ये विकास रोजगार की हानि गतिशीलता प्रतिबंधों और ज़ेनोफोबिक अनुभवों की बढ़ती दर के परिणामस्वरूप अस्तित्व में हैं। वास्तव में यह महामारी न सिर्फ एक आर्थिक तबाही है बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है जो असमानता की खाई को दीर्घावधि और मध्यम अवधि में बढ़ा रही है अगर इसे तत्काल कम करने के लिए उचित उपाय नहीं किए गए।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है वायरस के प्रसार को कम करने के लिए उठाए गए कड़े कदम दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। लॉकडाउन जैसी कठोर नीति ने श्रमिकों को अपने कार्यस्थलों के बजाय अपने विभिन्न घरों में रहकर काम करने पर प्रतिबंध लगाकर उत्पादकता के स्तर को प्रभावित किया है। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध यात्रा प्रतिबंध सार्वजनिक कार्यक्रमों की उपस्थिति और पर्यटकों के आकर्षण स्थल के दौरे पर प्रतिबंध ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में नकारात्मक योगदान दिया है जहां अधिकांश

व्यवसायों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में लगभग 90% की गिरावट का सामना करना पड़ा है। विशेष रूप से व्यवसाय सामाजिक व्यस्तताओं पर निर्भर हैं विशेष रूप से पर्यटन और मनोरंजन क्षेत्रों में मंदी का अनुभव हुआ है और उनके अधिकांश कर्मचारियों ने नौकरी की कमी और छंटनी के कारण अपनी आजीविका खो दी है। इससे उनके हताहतों की संख्या में खपत में गिरावट आई है और लोगों में खर्च करने को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है जिसके कारण यह हुआ कई व्यवसाय बंद हो जाएंगे और उनका पतन हो जाएगा। इसके स्थान पर अधिकांश देशों ने अपने सकल घरेलू उत्पाद को गिराते हुए आर्थिक विकास में भारी गिरावट का अनुभव करने का अनुमान लगाया है।

नतीजतन वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 के अंत में 3% की गिरावट आने की उम्मीद है और यह 2008 ;अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आए वैश्विक वित्तीय संकट से भी अधिक गंभीर है। हालाँकि वैश्विक आर्थिक दिग्गजों को महामारी के मद्देनजर सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्पेन इटली फ्रांस जर्मनी यूनाइटेड किंगडम जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 8.0%, 9.1%, 7.2%, 7.0%, 6.5%, 5.4% और संकुचन का अनुभव होगा। क्रमशः 5.9% ;अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), 2020)।

कुछ देशों में महामारी के मद्देनजर सरकारों ने अपने नागरिकों पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम किया। ग्रीनलैंड, अल्जीरिया, नाइजीरिया आदि देशों ने अपने नागरिकों को कोई आय सहायता प्रदान नहीं की। हालाँकि, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान आदि ने प्रभावित नागरिकों के वेतन का 50% से कम प्रदान किया, और कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे आदि ने प्रभावित नागरिकों के वेतन का 50% से अधिक प्रदान किया।

अनिवार्य रूप से, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना असंभव है। इसके बावजूद, सरकारों ने नागरिकों की दुर्दशा को कम करने और जीवन बचाने के लिए प्रोत्साहन पैकेजों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में धन पंप करने जैसी आर्थिक सुधार रणनीतियाँ तैयार की हैं। अनिवार्य रूप से, प्रतिक्रिया पैकेज महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन पहल हैं जो दुनिया भर की सरकारें मानव विकास में गिरावट और सीओवीआईडी -19 महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी को कम करने के लिए शुरू कर रही हैं। सरकारों द्वारा शुरू किए गए प्रमुख प्रोत्साहन पैकेजों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण, घरेलू उपभोग, सर्विसिंग और विनिर्माण उद्योग, बैंकों को तरलता सहायता, घरों और व्यवसायों के लिए धन का आवंटन, स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण समर्थन और नीतियों पर केंद्रित मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां शामिल हैं। छंटनी की लागत को कम करने पर लक्षित (बायर, बॉर्न, लुएटिके, और मुलर, 2020; चेंग, बार्सेलो, हार्टनेट, कुबिनेक, और मेसर्सचिमिड्ट, 2020; एल्गिन, बासबग, और यालामन, 2020)। जाहिर तौर पर, दुनिया भर में प्रोत्साहन पैकेजों का प्रकार महामारी के प्रति देशों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर भिन्न होता है।

दुनिया भर में सरकारों द्वारा प्रदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे अधिक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने वाले देश हैं बहरीन, माल्टा, ऑस्ट्रिया, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, ओमान, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी और मलेशिया, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन पैकेज वाले शीर्ष 10 देशों में 31.30, 25.61%, 25.11 तक हैं। क्रमशः 22.91%, 22.59%, 22.59%, 19.61%, 18.65%, 17.29% और 16.42%। स्पष्ट रूप से, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों के लिए सरकारों की पसंद महामारी के

परिणामस्वरूप हुई आर्थिक मंदी को कम करने के लिए उनकी आर्थिक कठोरता और संप्रभु क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर थी।

गरीबी उन्मूलन पर COVID-19 का प्रभाव सामान्य न्यूनतम वर्ग और मजबूत न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन दोनों तरीकों से विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि विभिन्न देशों में लॉकडाउन के प्रभाव और कुल पुष्टि किए गए मामलों को देखते हुए, COVID-19_ महामारी ने गरीबी उन्मूलन पर विपरीत प्रभाव डाला। विशेष रूप से, लॉकडाउन (कठोरता) ने मानव पूंजी विकास को क्रमशः 0.015 और 0.003 सूचकांक स्कोर तक खराब कर दिया। हालाँकि, सरकार के कड़े कदमों से नौकरियाँ खोने, शिक्षा की हानि, स्वास्थ्य की हानि और रोजगार योग्य उद्यमों से आय की हानि के माध्यम से मानव विकास में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा, व्यवसायों और रोजगार के पतन के कारण सरकारों के लिए राजस्व की हानि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के माध्यम से मानव विकास में सुधार के प्रयासों को रोक सकती है और गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकती है।

दिलचस्प बात यह है कि कोविड-19 महामारी के कारण हुई कुल मौतों ने गरीबी उन्मूलन प्रयासों और मानव विकास सूचकांक पर सकारात्मक प्रभाव डाला। इस विकास का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि प्रक्षेपवक्र गरीबी उन्मूलन के अनुकूल नहीं है; इसलिए, जनसंख्या वृद्धि का गरीबी उन्मूलन पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

इसके विपरीत, अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि गरीबी उन्मूलन प्रयासों को बढ़ाकर, आर्थिक विकास को लगातार बढ़ाया जाना चाहिए, और जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। विशेष रूप से, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत अंक या $1 की वृद्धि मानव विकास सूचकांक के 0.049 और 0.124 सूचकांक स्कोर में तब्दील हो जाती है; इस प्रकार, गरीबी उन्मूलन। इसके अलावा, जनसंख्या वृद्धि में प्रतिशत अंक की कमी मानव विकास के सूचकांक स्कोर 0.011 और 0.003 में तब्दील हो सकती है, जिससे गरीबी उन्मूलन हो सकता है।

आर्थिक विकास पर COVID-19 का प्रभाव आर्थिक विकास के संबंध में, संक्रमण को कम करने के लिए बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए कठोरता के स्तर को देखते हुए, COVID-19 महामारी का आर्थिक विकास पर विविध प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, बढ़ती सख्ती सकारात्मक रूप से बढ़ती आर्थिक वृद्धि का समर्थन करती है जहाँ मृत्यु में वृद्धि हुई है।

इसलिए, कठोरता सूचकांक स्कोर में प्रतिशत आधार बिंदु वृद्धि से आर्थिक वृद्धि (प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद) क्रमशः $0.025 और $0.008 तक बढ़ सकती है, जबकि कुल पुष्टि किए गए मामलों में क्रमशः 0.030% और 0.004% की कमी हो सकती है।

मानव विकास के सूचकांक स्कोर में प्रतिशत आधार बिंदु वृद्धि से आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $6.023 और $7.257 हो सकता है। नमूना अवधि के भीतर मानव विकास पर आर्थिक वृद्धि के संबंध में महामारी का प्रभाव क्रमशः $6.023 प्रति व्यक्ति और $7.257 प्रति व्यक्ति बताया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि महामारी के संबंध में दर्ज की गई कुल मौतें आर्थिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, जो जनसंख्या में कमी की तात्कालिकता का संकेत देती हैं। इसके अलावा, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति की दिशा में ठोस प्रयास किये जाने चाहिए।

<u>लॉकडाउन और प्रतिबंधों का प्रभाव</u> अतीत में जिस हद तक स्थानीयकृत लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाए गए हैं, उससे आर्थिक सुधार की समयबद्धता प्रभावित हुई है। पूरे वर्ष निरंतर राजकोषीय प्रोत्साहन की गुंजाइश है। कुछ हद तक, यदि व्यवसायों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो मौद्रिक प्रोत्साहन भी संभव है। दूसरी लहर ने भारत की नाजुक आर्थिक सुधार को पीछे धकेल दिया है। बढ़ती असमानता और तनावपूर्ण घरेलू बैलेंस शीट ने सुधार को बाधित किया है। 2019-20 में केवल 4% की वृद्धि से लेकर 2020-21 में 7-8% की गिरावट से लेकर 2021 में एक और कम आर्थिक विकास सुधार की ओर बढ़ने तक, भारत को उसके सभी ट्रैक पर लगभग रोक दिया गया है। इसलिए, राजकोषीय नीति को कमजोर व्यवसायों और परिवारों को आर्थिक सुधार की ओर ले जाने के लिए उदारतापूर्वक मदद करनी चाहिए। परिकल्पना:

यदि प्रकोप समय के साथ बिगड़ता है, या यदि मामले संख्या बहुत अधिक है, तो इससे भारत की आर्थिक और राजकोषीय सुधार के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। एक बार जब कोविड लहरें कम हो जाएंगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी रिकवरी फिर से शुरू करनी चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में प्रति व्यक्ति आय के समान स्तर पर अपने साथियों की तुलना में तेज गति से बढ़ती रहेगी। नकारात्मक पक्ष में, सरकारी राजस्व में कम जोरदार वसूली होगी और गंभीर नकारात्मक परिदृश्य में अतिरिक्त राजकोषीय खर्च करना पड़ सकता है। संक्रमण की प्रारंभिक धारा और संबंधित लॉकडाउन उपायों से कमोडिटी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। 2021 की दूसरी छमाही में इसमें जोरदार सुधार हुआ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार से इसकी संभावना कम हो गई है कि 2020 जैसी तेज कीमत में गिरावट दोबारा होगी। जब प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दबी हुई मांग में मजबूत सुधार होने की संभावना है, जैसा कि 2020 में देखा गया था। कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारतीय बुनियादी ढांचे के लिए अन्यथा मजबूत सुधार को चुनौती दी है। जैसे-जैसे उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, वे विनियमित रिटर्न, निश्चित टैरिफ और मांग में त्वरित सुधार के कारण कमाई बनाए रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय यातायात सुधार में एक और वर्ष की देरी होने की संभावना के कारण हवाई अड्डों को सबसे अधिक खतरा है। यदि सरकार गतिशीलता पर प्रतिबंधों की गंभीरता और दायरा बढ़ाती है तो इससे मजबूत घरेलू सुधार में बाधा आ सकती है। विनाशकारी 2020 के बाद एक मजबूत रिकवरी की आवश्यकता है। जैसे-जैसे प्रकोप बदतर होता गया, राज्य सरकारों ने प्रतिबंधात्मक लॉकडाउन उपाय लागू किए, जिससे उभरती हुई आर्थिक रिकवरी रुक गई। डाउनग्रेड एक चेतावनी है कि आर्थिक सुधार को हल्के में न लें। टीकाकरण की धीमी गति भारत की आर्थिक सुधार पर बोझ पड़ने की संभावना है। विशेषकर वित्त वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही में कई क्षेत्रों में भारतीय रिकवरी जोरदार रही है। घरेलू हवाई यातायात में रुकावट और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में कमी ने हवाई अड्डों के लिए रिकवरी को खत्म कर दिया है। कोविड लहर ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को बुरी तरह प्रभावित किया है। इससे बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार में देरी हुई है। गतिशीलता सामान्य स्तर से 50-60% तक कम हो गई है। इसलिए, लोग अधिक घर पर रह रहे हैं और कम खर्च कर रहे हैं। इस साल के अंत में रिकवरी जोर पकड़ेगी। मार्च के दौरान भारत की उभरती आर्थिक सुधार ने सरकारी राजस्व को मजबूत किया।

परिकल्पना 1

बिजली क्षेत्र: भारतीय बिजली क्षेत्र भारी राजस्व उत्पन्न करेगा और यह भारत की जीडीपी की वसूली को ट्रैक करेगा।

परिकल्पना 2

हवाई अड्डे: दूसरी लहर ने भारत के हवाई पुनर्प्राप्ति यातायात को खतरे में डाल दिया है। घरेलू यात्री यातायात प्री-कोविड स्तर से 75% कम हो गया है। सबसे खराब स्थिति में ट्रैफ़िक रिकवरी अनुमान से 10% कम हो सकती है। कमज़ोर यातायात हवाई अड्डों के नकदी प्रवाह को प्रभावित करता है। थोड़े व्यवधान के बाद सड़क यातायात में तेजी से सुधार होगा। वाणिज्यिक वाहन यातायात में बेहतर लचीलापन देखने को मिलेगा क्योंकि यह रसद और आवश्यक सेवाओं का समर्थन करता है।

परिकल्पना 3

बंदरगाह: आयात की मात्रा में मामूली सुधार देखा जाएगा। कच्चे और कोयला खंड की तुलना में उर्वरक और कंटेनर अधिक गति से बढ़ेंगे।

परिकल्पना 4

बुनियादी ढाँचा: परिचालन नकदी प्रवाह अधिकांश बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं जैसे पानी, सीवेज, बांध और प्राकृतिक गैस खंडों को पुनर्प्राप्त करेगा। वित्तीय वर्ष 2022 में क्रेडिट हानि कुल ऋण के 2.2% पर उच्च रहेगी, 2023 में 1.8% तक पहुंचने से पहले। भारत की मजबूत आर्थिक सुधार और आर्थिक संकट के प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकारों और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम बैंकों पर बोझ कम हुआ है. इसके अतिरिक्त, बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए पूंजी जुटाई है। इससे कोविड संबंधी नुकसान से राहत मिलेगी। बड़े पैमाने पर नौकरी छूटने और औपचारिक क्षेत्र में वेतन कटौती के साथ कमजोर खपत से बैंकिंग क्षेत्र के ऋण और 'क्रेडिट कार्ड' ऋण प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वसूली दर कम हो गई है। इससे कमजोर ऋणों में वृद्धि हो सकती है। यदि हमें वी-आकार, के-आकार या डब्ल्यू-आकार के रास्तों के विपरीत निरंतर और वास्तविक आर्थिक विकास की ओर बढ़ना है, तो राज्यों और केंद्र को टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के लिए अपनी "सहकारी संघवाद" योजना के माध्यम से एक सहकारी रणनीति की दिशा में काम करने की आवश्यकता है।

पिछले साल, सरकार ने आजीविका के बजाय जीवन को चुना। पूर्व की सुरक्षा का चयन करने से, सितंबर में कोविड 1.0 में देरी हुई और इसकी तीव्रता अनुमान से बहुत कम थी। जनवरी 2021 तक सरकार ने कोविड-19 पर जीत की घोषणा कर दी थी. आर्थिक सुधार के लिए पहला खतरा क्षेत्रीय मामले हैं जिनके परिणामस्वरूप लॉकडाउन को और बढ़ाया जा रहा है और इसलिए वे आर्थिक सुधार की गति को सीमित कर रहे हैं। दूसरा खतरा वैक्सीन आपूर्ति से उत्पन्न होने वाली टीकाकरण दर है। हमारी श्रम शक्ति के एक बड़े हिस्से का टीकाकरण किए बिना, यह खतरा है कि वायरस हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था को बाधित कर देंगे। यह दुनिया भर में कोविड-19 के मामलों से स्पष्ट है।

अनुसंधान क्रियाविधि

क्रियाविधि

व्यापक अर्थशास्त्र पर COVID-19 महामारी के प्रभाव से संबंधित कुछ विद्वतापूर्ण कार्य देश-स्तर और वैश्विक स्तर से सामने आए हैं। विशेष रूप से, कुछ विद्वानों ने अमेरिकी शेयर बाजार पर महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया और अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रभावों का गंभीर मूल्यांकन किया (पैगानो, वैगनर, और ज़ेचनर, 2020)। एक अन्य अध्ययन में, लुडविगसन, मा, और एनजी (2020) ने VAR ढांचे का उपयोग करके व्यापक अर्थव्यवस्था पर COVID-19 महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया।

अपने निष्कर्षों से, उन्होंने तर्क दिया कि COVID-19 महामारी के झटके पिछली महंगी प्रतिकूलताओं से संबंधित हैं। बहु-क्षेत्रीय मॉडल में, बकाए। और फरही (2020) ने अमेरिका के समग्र डेटा पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए एक गैर-रैखिकता दृष्टिकोण का उपयोग किया। उन्होंने सुझाव दिया कि महामारी से आए झटकों को गैर-रैखिक दृष्टिकोण से कम किया जा सकता है। जैसा कि मैककिबिन और फर्नांडो (2020) ने पहचाना है, अनजाने में, COVID-19 महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, जो पिछले वर्षों में प्रकट होने की संभावना है।

आपूर्ति और मांग पक्ष में व्यवधान के कारण, महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नौकरियों के नुकसान, आय की हानि, स्वास्थ्य और मानव पूंजी विकास (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2020) को प्रभावित करने वाली शिक्षा में गिरावट का कारण बना दिया है। इसके अलावा, आर्थिक मंदी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई (विश्व बैंक, 2020)। इस अध्ययन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और गरीबी उन्मूलन पर महामारी के प्रभाव को मापना है। इसलिए, अध्ययन अपने अर्थमितीय और अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए नीचे दिए गए मॉडल का निर्माण करता है; कोविड-महामारी के लोच गुणांक, और बहिर्जात चर के रूप में मानव विकास। मॉडल में होने वाली अपेक्षित त्रुटि शब्द या स्टोकेस्टिक गड़बड़ी का गठन करता है। इसके अलावा, मैं 170 देशों के क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करता हूं, और टी अध्ययन के तहत अवधि का प्रतिनिधित्व करता है; इस प्रकार, 31/12/2019 से 19/10/2020 तक। अनुमान में सामान्य न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन विधि का उपयोग किया जाता है।

पैनल में क्रॉस-अनुभागीय विविधता और अंतर्जात मुद्दों की जांच करने के लिए ओएलएस की कमजोरी के कारण मजबूत न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन विधि का उपयोग एक मजबूत जांच के रूप में किया जाता है। ओएलएस अनुमान के लिए एक उपयुक्त तरीका है क्योंकि एक सह-एकीकरण संबंध स्थापित नहीं किया जा सका।

इस अध्ययन के लिए उपयोग किया गया डेटा ourWorldinData.com से निकाला गया था। COVID-19 चर के लिए डेटा की लंबाई 31/12/2019 से 19/10/2020 तक फैली हुई है, और मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के लिए डेटा की लंबाई 1990 से 2017 तक चलती औसत मान है।

आश्रित चर गरीबी उन्मूलन को मापने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में मानव विकास सूचकांक और आर्थिक विकास को मापने के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) हैं। स्वतंत्र चर COVID-19 महामारी है, और इसे मापने के लिए तीन प्रॉक्सी का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार कठोरता सूचकांक, दुनिया भर में कुल पुष्टि किए गए मामले और दुनिया भर में कुल पुष्टि की गई मौत।

विश्लेषण:

अध्ययन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभावों का आकलन करना था, जिसमें स्पष्ट रूप से आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन प्रयासों पर जोर दिया गया था। इसके विपरीत, महामारी प्रभाव चर (कठोरता

सूचकांक, कुल मामले और कुल मौतें) और आर्थिक विकास पर डेटा (प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद) के लिए 31/12/2020 से 19/10/2020 तक 170 देशों के एक पैनल का नमूना लिया गया था। और गरीबी उन्मूलन (मानव विकास सूचकांक) में 1990 से 2017 तक चलती औसत का उपयोग किया गया। अध्ययन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कुछ अर्थमितीय दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जैसे सामान्य न्यूनतम वर्ग पूलित प्रतिगमन विधि और महामारी के लंबे समय का अनुमान लगाने के लिए सबसे मजबूत न्यूनतम वर्ग प्रतिगमन विधि। प्रभाव चलाएँ. अध्ययन में पाया गया कि महामारी का आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। विशिष्ट रूप से, यह देखा गया कि उठाए गए कड़े कदमों और दर्ज किए गए मामलों की संख्या का गरीबी उन्मूलन प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जबकि कड़े उपाय में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि से मानव विकास सूचकांक में प्रति दिन 0.015 और 0.003 सूचकांक अंकों की कमी हो सकती है, जिसका अर्थ है अर्थशास्त्र और वित्त पत्र, 2021, 8(1): 32-43 का अर्थ है गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में गिरावट , जबकि COVID-19 मामलों में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि से मानव विकास सूचकांक में प्रति दिन 0.049 और 0.124 सूचकांक स्कोर में कमी आ सकती है, जिसका अर्थ है गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में गिरावट। इसके अलावा, कुल मृत्यु में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि दिलचस्प रूप से मानव विकास पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है जिससे गरीबी उन्मूलन होता है। दूसरी ओर, जैसा कि अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है, कठोरता उपायों को बढ़ाने से आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शायद, कठोरता उपायों में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि से प्रति दिन आर्थिक विकास में $0.025 और $0.008 की वृद्धि हो सकती है, जबकि कुल पुष्टि किए गए मामलों में क्रमशः 0.030% और 0.004% की कमी हो सकती है। मानव विकास के सूचकांक स्कोर में प्रतिशत आधार बिंदु वृद्धि से आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $6.023 और $7.257 हो सकता है। नमूना अवधि के भीतर मानव विकास पर आर्थिक वृद्धि के संबंध में महामारी का प्रभाव क्रमशः $6.023 प्रति व्यक्ति और $7.257 प्रति व्यक्ति बताया जा सकता है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिक निवेश को मानव विकास, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के लिए रोजगार सृजन में सुधार के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए घरेलू खपत और फर्मों के निवेश में वृद्धि हो सके। इसके अलावा, सरकारों को आर्थिक सुधार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति समर्थन के माध्यम से महत्वपूर्ण राजकोषीय स्थान बनाना चाहिए, यह एक त्वरित प्रतिक्रिया है (विश्व बैंक, 2020)। उपयोगी और समय पर पुनर्प्राप्ति के लिए एक समन्वित और व्यापक क्रॉस-कंट्री नीति प्रतिक्रिया की आवश्यकता है (चुडिक एट अल।, 2020)।

एक विश्वसनीय टीका विकसित होने तक, जीवन बचाने, स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार करने और गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे कठोरता, सामाजिक दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए। वैश्विक कोविड-19 महामारी अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और कमजोर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। शायद, सरकारों, नीति निर्माताओं और विकास भागीदारों को एक मजबूत और टिकाऊ पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए त्वरित नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है। हालाँकि, व्यावहारिक और आपातकालीन सामाजिक-आर्थिक प्रतिक्रियाओं के बिना, महामारी के झटके वैश्विक संकट को बढ़ा देंगे, सबसे महत्वपूर्ण रूप से, आजीविका और जीवन को अधिक विस्तारित अवधि के लिए खतरे में डाल देंगे (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 2020)। अध्ययन की सीमा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और मानव विकास

सूचकांक के दैनिक डेटा की अनुपलब्धता से उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग आश्रित चर के रूप में किया गया था। इसके अलावा, अन्य कारक महामारी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं; इसलिए भविष्य के अध्ययनों में उन चरों को शामिल किया जाना चाहिए जो उस रिश्ते में हस्तक्षेप कर सकते हैं। साथ ही, इस अध्ययन के आयोजित होने के बाद से कुछ देशों की स्थिति बदल गई है। इसलिए, अध्ययन की समय अवधि एक संभावित सीमा है जो महामारी स्थितियों की संपूर्ण गतिशीलता को कम नहीं कर सकती है।